

प्रधानमंत्री का संबोधन

पीएम मोदी ने जिस तरह अपनी सरकार की उपलब्धियों का सविस्तार जिक्र किया, उससे साफ है कि वे चुनावी मोड में आ चुके हैं।

नए भारत के निर्माण का संकल्प



भवदीप कांग

bhavkang@gmail.com

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में यह संदेश निहित था कि लोगों को सरकारी संस्थाओं या राजनीतिक दलों के बजाय उन पर और उनके 'न्यू इंडिया' के विजन पर भरोसा करना चाहिए। उन्होंने तंत्र पर जन की महत्ता प्रतिपादित करते हुए राय जताई कि सामूहिक प्रतिबद्धता से ही वर्ष 2022 तक 'न्यू इंडिया' बनाने का सपना साकार हो पाएगा।

स्वाधीनता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से अपने अब तक के सबसे संक्षिप्त संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2019 के आम चुनाव के लिए अपनी जमीन और पुख्ता करते नजर आए। जहां उन्होंने अपनी तमाम उपलब्धियों का सविस्तार जिक्र किया, वहीं की नीतियों के बारे में संशय दूर करने की भी कोशिश की। हमेशा की तरह उन्होंने लोगों के साथ सीधा संपर्क कायम किया, उन्हीं के सामाजिक-सांस्कृतिक संदर्भों के अनुरूप अपने भाषण का ताना-बाना बुना और तंत्र के ऊपर 'लोक' की महत्ता स्थापित की।

गौरतलब है कि उन्होंने अपना यह भाषण आमजन के सुझाव के मुताबिक तैयार किया था। उन्हें देशभर से 10,000 से ज्यादा सुझाव मिले थे कि वे इस बार किन-किन विषयों पर बोलें। यह सहभागितापूर्ण लोकतंत्र पर जोर देने की प्रधानमंत्री की सोच के अनुरूप भी है, जहां पर वे देश के प्रत्येक नागरिक को 'टीम इंडिया' का सदस्य मानते हैं और चाहते हैं कि देश की समृद्धि में उसकी भी सहभागिता हो। उनके भाषण में यह संदेश निहित था कि लोगों को सरकारी संस्थाओं या राजनीतिक दलों के बजाय उन पर और उनके 'न्यू इंडिया' के विजन पर भरोसा करना चाहिए।

यह विजन है क्या? एक सुरक्षित, समृद्ध और मजबूत राष्ट्र बनाने का लक्ष्य नया नहीं है। तमाम सरकारें सबके लिए खाद्य सुरक्षा, आवास, शिक्षा, बिजली, स्वास्थ्य, स्वच्छता आदि मुहैया कराने पर जोर देती हैं। और फिर हर प्रधानमंत्री ने अतीत में किसानों की आय बढ़ाने, युवाओं को रोजगार देने, भ्रष्टाचार व आतंकवाद से मुक्ति दिलाने, सामाजिक सद्भाव और सीमा सुरक्षा सुदृढ़ करने का वादा किया। फर्क सिर्फ यह है कि मोदी लोगों को यह यकीन दिलाने में कामयाब हैं कि 'न्यू इंडिया' का यह विजन उनकी पहुंच में है और यदि लोग उनके साथ मिलकर काम करें तो उनकी सरकार द्वारा शुरू किए गए प्रयासों के नतीजे वर्ष 2022 में अवश्य परिलक्षित होंगे, जब देश अपनी आजादी की 75वीं सालगिरह मनाएगा। उनके द्वारा वर्ष 2022 पर और युवाओं (जो अगले साल 18 साल के होंगे और 2019 में वोट देंगे) पर जोर देने में यह संदेश निहित है कि

इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए उनकी सरकार का बरकरार रहना अहम है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 'सुराज', 'अंत्योदय' और 'राष्ट्र' की अवधारणाएं 'राज्य' की अवधारणा से अलग हैं, जिसकी झलक मोदी के इस भाषण में भी नजर आई। उन्होंने जन की महत्ता प्रतिपादित करते हुए राय जताई कि जनता ही विकास का इंजन होती है, न कि 'चलता है' रवैया अपनाते वाली सरकारें। उन्होंने स्पष्ट कहा कि कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। एक गिलहरी भी परिवर्तन प्रक्रिया का हिस्सा बनती है। हमारी सामूहिक



प्रतिबद्धता से ही 2022 में 'न्यू इंडिया' बनाने का सपना साकार हो पाएगा। प्रधानमंत्री मोदी का राष्ट्रवाद पं. दीनदयाल उपाध्याय के 'एकात्म मानववाद' दर्शन के अनुरूप है और इसी वजह से इसमें एक मजबूत नैतिक घटक भी है। एक मजबूत राष्ट्र के निर्माण में 'यज्ञ' और 'शुद्धि' की अपनी अहमियत है। नैतिकता और आत्म-त्याग के जरिए लोग देश में व्यापक बदलाव ला सकते हैं। इसके लिए उन्होंने 'त्याग' की उस मुहिम का हवाला भी दिया, जिसके तहत लाखों लोगों ने स्वेच्छा से गैस सबसिडी छोड़ दी।

राजनीतिज्ञ व समाजशास्त्री, जो यह नहीं समझ सके कि गरीब व मध्यम वर्ग के लोगों ने नोटबंदी और जीएसटी के क्रियान्वयन को दिक्कतें सहने के बावजूद बगैर किसी

प्रतिरोध के कैसे स्वीकार कर लिया, उन्हें निश्चित ही पंडित दीनदयाल के विचारों का अध्ययन करना चाहिए, जिनसे कि मोदी प्रेरणा लेते हैं। यही वजह है कि मोदी का जोर ईमानदारी, त्याग और सामूहिक शक्ति और जन-संकल्प आदि पर होता है। इसीलिए वे ऐसा 'न्यू इंडिया' बनाना चाहते हैं, जो अपनी इस विरासत से गहरे तक जुड़ा हो, पर साथ ही साथ लेकिन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आधुनिक विज्ञान और तकनीक के इस्तेमाल में पूर्ण सक्षम हो। अपने इस संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार भ्रष्टाचार व काले धन के



खिलाफ लड़ाई को लेकर स्पष्ट तस्वीर पेश की। उन्होंने चार बातें कहीं। एक, इन तीन वर्षों में 1.25 लाख करोड़ रुपए का काला धन जब्त किया गया और नोटबंदी के बाद बैंकों में जो 3 लाख करोड़ रुपए जमा हुए, उनमें से 1.75 लाख करोड़ की राशि शक के घेरे में है। उन्होंने पुनः यकीन दिलाया कि भ्रष्टाचारी बख्खो नहीं जाएंगे। दो, आयकर रिटर्न भरने वालों संख्या में तीव्र उछाल (दोगुने से ज्यादा), जो दर्शाता है कि काले धन का प्रवाह सुस्त पड़ा है। तीसरी बात, तीन लाख ऐसी कंपनियों का पता चला, जो हवाला सौदों में लिप्त थीं और ऐसी पौने दो लाख कंपनियों का पंजीयन रद्द किया जा चुका है। चार, 800 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्तियां जब्त की जा चुकी हैं। निहितार्थ यह है कि मोदी सरकार ईमानदारी व शुचिता

पर जोर देते हुए शासन की कार्य-संस्कृति में आमूल बदलाव ला रही है, पिछली सरकारें जो करने में नाकाम रही थीं।

प्रधानमंत्री मोदी द्वारा अपनी सरकार की नीतियों व उपलब्धियों का सविस्तार जिक्र करने से साफ है कि वह चुनावी मोड में आ चुके हैं। उन्होंने मौजूदा एनडीए सरकार की पिछली सरकारों से तुलना करते हुए इस बात को इंगित किया कि पहले जो परियोजनाएं बरसों से लंबित थीं, अब उन पर तेजी से काम हो रहा है। यह भी महत्वपूर्ण है कि उन्होंने इशारों-इशारों में ये भी बताया कि उनकी सरकार तीन तलाक के खिलाफ है। इस तरह उन्होंने एक बार फिर खुद को पिछली सरकारों से अलग साबित किया, जो कट्टरपंथी इस्लामिक समूहों के दबाव के आगे झुकती आई हैं।

कश्मीर की हालिया अशांति के मद्देनजर प्रधानमंत्री ने एक बार फिर नरम रवैया अपनाया। उन्होंने कहा कि समस्या का हल न गाली से होगा, न गोली से, बल्कि कश्मीर के लोगों को गले लगाने से होगा। इसके साथ-साथ उन्होंने आतंकवादियों व वाम चरमपंथियों के खिलाफ सख्त रवैया भी दर्शाया।

कुछ लोग कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में नारी सुरक्षा, सरकारी एजेंसियों द्वारा सेवाओं की खराब आपूर्ति, रोजगार के अवसरों की कमी, आर्थिक सुस्ती, चीन के बढ़ते खतरे समेत और भी कई समस्याओं का जिक्र नहीं किया। वह इन अवरोधों से निजात पाने का कोई रोडमैप भी पेश नहीं कर पाए।

बहरहाल, कोई कुछ भी कहे, पर यह तो मानना होगा कि मोदी जिस तरह आमजन के साथ जुड़ाव कायम करते हैं, उसका कोई सानी नहीं। वे पौराणिक वृतांत, प्राचीन परंपराओं और सामाजिक रीति-रिवाजों से जुड़ी कथाओं का जिक्र छेड़ते हुए लोगों को इस बात के लिए प्रेरित करते हैं कि किस तरह इन विचारों को अपने रोजमर्रा के जीवन में अपनाते हुए व्यापक बदलाव लाया जा सकता है। और उनकी इसी खूबी में उनकी सतत चुनावी सफलताओं का रहस्य निहित है।

(लेखिका पत्रकार हैं।
ये उनके निजी विचार हैं)